

//- सुविचार -//

गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूढ़ तो टीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती...

सूर्योदय

उदय : 5.09 प्रातः

अस्त : 6.21 संध्या

प्रदेश का मौसम

स्थान	अधिकतम	न्यूनतम
रांची	36.0	25.0
जमशेदपुर	36.0	27.0
रामगढ़	40.1	28.1
डालटनगंज	42.0	30.0

बराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत

सरायकेला। सरायकेला-खरसावां जिले के घटना चांडिल थाना क्षेत्र में टाटा रांची मुख्य मार्ग पर सहरखेड़ा पुलिया के सामने एक अनियंत्रित बराती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन पर सवार सभी लोग बराती थे। इस हादसे में बरात में शामिल 4 लोगों की मौके पर मौत हो गयी, जबकि 15 बराती घायल हो गये। हादसे की जानकारी होते ही ग्रामीण और पुलिस ने आनन-फानन में घायलों को जमशेदपुर अस्पताल भेज दिया, जबकि पोस्टमार्टम के लिए तीनों शवों को सरायकेला भेजा गया। बताया गया कि बरात रामगढ़ से ईचागढ़ के दारुदा जा रहा था उसी दौरान ये घटना हुई। वहीं, जानकारी मिली की पिकअप वैन मुखिया उम्मीदवार भीम सिंह मुण्डा का प्रचार वाहन है। थाना प्रभारी शम्भु शरण ने फोन पर जानकारी दी कि घायलों में 5 की स्थिति काफी नाजुक है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाई में जुटी हुई है।

देश में कोरोना के मिले 2827 नये मरीज

नयी दिल्ली : देश में पिछले 24 घंटे के दौरान गुरुवार सुबह आठ बजे तक कोरोना संक्रमित 2,827 नए मरीज मिले हैं। इस अवधि में कोरोना महामारी की मात देने वालों की संख्या 3,230 रही, जबकि कोरोना संक्रमित 24 मरीजों की मौत हो गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अबतक कुल 4 करोड़ 25 लाख 70 हजार 165 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा रिकवरी दर 98.74 प्रतिशत है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 19,067 है। दैनिक संक्रमण दर 0.60 प्रतिशत है।

राजीव कुमार होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त

नयी दिल्ली : चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वह 14 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे सुशील चन्दा का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिंजिजू ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने राजीव कुमार को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने सविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) के अनुसरण में राजीव कुमार को 15 मई, 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। चुनाव आयोग में कार्यभार संभालने से पहले राजीव कुमार लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजीव कुमार 1984 बैच के बिहार/झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। फरवरी 2020 में वह प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।

राजनीति

धूम-धड़ाके के साथ 17 मई को घर वापसी की तैयारी

भाजपा में फिर प्रवीण, मजबूत होंगे बाबूलाल

गौतम चौधरी

रांची : जनता दल (यूनाइटेड) को तिलांजलि देने के बाद 17 मई को ताम-झाम के साथ प्रवीण सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रवीण की घर वापसी से बाबूलाल मरांडी के जमाने वाली भाजपा एक बार फिर से आकार ग्रहण कर सकती है। वैसे भी भाजपा की वर्तमान टीम में बाबूलाल समर्थकों का दबदवा है। प्रदीप यादव को छोड़ लगभग सभी बाबूलाल समर्थक अब भाजपा में हैं। यही कारण है कि प्रवीण सिंह की वापसी की आहट से भाजपावी अंतःपुर में इस बात की जबर्दस्त चर्चा है कि अब जी-4 मजबूत होगा।

मालूम हो कि बाबूलाल मरांडी ने जब 24 सितंबर, 2006 को झारखंड

दैनिक आदित्यर्षा तमसः परस्मात्		प्रदेश के साथ पूरा देश...			
अंदर के पृष्ठों पर ♠❖	3 राजधानी	5 झारखंड	6 अभिव्यक्ति	7 झारखंड	
रांची, शुक्रवार, 13 मई 2022, वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी, विक्रम संवत- 2079 वर्ष-08 अंक-29 पृष्ठ-12, मूल्य - 3 रुपये					

झारखंड राज्य व केन्द्र सरकार में टकराव बढ़ा, सत्ता की लंबी लड़ाई का संकेत

जेएमएम आक्रामक, कांग्रेस हेमंत के साथ

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइंस लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस पर मुश्किलों में घिरेते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इशारे-इशारों में इसे केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दबाव में उठाया गया कदम करार देते हुए कहा है- मैं न झुकूंगा और न ही कार्यों की तरह भागूंगा। सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने यूक्रेन पर रूसी हमले की तर्ज पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गयी राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से रूसी हमले का यूक्रेन की ओर से कराार जवाब दिया जा रहा है, उसी तरह से जेएमएम गठबंधन के कार्यकर्ता भी भाजपा के खिलाफ लंबी लड़ाई के जज्बे का इजहार किया है।



जेएमएम ने कहा-राजनीतिक साजिश

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 2 मई को नयी दिल्ली से एक विशेष मैसेंजर भेज कर जब सीएम हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय को खनन लीज मामले को लेकर स्पष्टीकरण से संबंधित नोटिस भ्रमाया गया और जवाब देने के लिए एक सप्ताह 10 मई तक का समय दिया गया, तो राजनीतिक महकमे में इस बात की चर्चा शुरू हो गयी कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 ए के तहत हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने से संबंधित मामले में आयोग जल्द ही राज्यपाल रमेश बैस को मंतव्य सीप देगा। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने कानूनी परामर्श लेना शुरू किया। इस दौरान जेएमएम के कई नेता दिल्ली पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के वरिय अधिवक्ताओं के साथ ही कई रिटायर न्यायाधीश न्यायमूर्ति से भी लौगल ओपिनियन लिया। लौगल ओपिनियन लेने के बाद जब जेएमएम नेताओं को यह महसुस हुआ कि इस मसले को न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी निपटने की जरूरत है। इसके बाद जेएमएम-कांग्रेस नेता आक्रामक हो गये। जेएमएम नेताओं ने रांची में भाजपा मुख्यालय के घेराव का प्रयास किया, वहीं सभी जिला मुख्यालयों में पुतेले फूके गये।

अदालत का दरवाजा खटखटाने का संकेत

जेएमएम और कांग्रेस के नेता एक ओर न सिर्फ इस मामले में सड़क पर उतर अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप लगाते हुए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेएमएम विधायक सुदित्य कुमार सोनू ने यह साफ कहा है कि यदि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मतव्य दिया जाता है, तो पार्टी इसकी कानूनी समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखाटेगी।

कांग्रेस जेएमएम के साथ

इधर, चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन के सभी विधायकों ने एकजुट रहने का दावा किया है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के मतव्य पर बरहेट विधानसभा से निर्वाचित हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यताता पर आंव भी आती है, इसके बावजूद जेएमएम-कांग्रेस में बिना किसी बड़े टूट हुए महागठबंधन सरकार पर कोई खतरा बनते नजर आ रहा है।

ऑपरेशन खान. अपने बयान से मुकरा सीए सुमन कुमार, ईडी से कहा

बरामद नगदी पूजा सिंघल की

● सीए की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ायी गयी



रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में सीए सुमन कुमार सिंह ने कई खुलासे किए हैं। ईडी समक्ष सुमन कुमार अपने पूर्व के बयान से मुकर गया और पूछताछ में बताया है कि उनके घर से बरामद अधिकांश नगद राशि आईएसएस पूजा सिंघल की है, जो उनके निर्देश पर एक्त्रित की गयी थी। सीए ने बताया है कि पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक प्रसिद्ध बिल्डर को तीन करोड़ नकद दिये गये थे। पूजा सिंघल ने पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के महत्वपूर्ण मामलों जैसे निर्माण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारी भुगतान आमतौर पर नकद में प्राप्त किया गया था।

पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ा गया है। अब उनसे 16 मई तक पूछताछ होगी। ईडी की ओर से सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद गुरुवार को उसे ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ईडी ओर से 9 दिनों की रिमांड की मांग की गयी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड अवधि की मंजूरी दी। इससे पहले 8 मई को ईडी ने सुमन को रिमांड पर लिया था और 5 दिनों तक पूछताछ करने के बाद आज उसे अदालत में पेश किया गया, लेकिन पूछताछ पूरी नहीं होने के कारण रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया।

श्रीलंका संकट : रानिल विक्रमसिंघे बने प्रधानमंत्री

- पांचवीं बार संभाली देश की कमान**
- संसद में है केवल एक सीट**

कोलंबो : अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर का सामना कर रहे श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को गुरुवार को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। रानिल विक्रमसिंघे के पास 225 सदस्यीय संसद में केवल एक सीट है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के 73 वर्षीय नेता



विक्रमसिंघे ने बुधवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से बात की थी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के

73 वर्षीय नेता विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे पहले

दोनों ने बुधवार को बंद कमरे में बातचीत की थी। श्रीलंका के चार बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे को अक्तूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि, दो महीने बाद ही सिरीसेना ने उन्हें इस पद पर बहाल कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक, सत्तारूढ़ श्रीलंका पोटुजाना पेरामुना (एसएलपीपी), विपक्षी समूगी जन बालावेगाया (एसजेबी) के एक धड़े और अन्य कई दलों ने संसद में विक्रमसिंघे के बहुमत साबित करने के लिए अपना समर्थन जताया है।

मुख्तार अब्बास नकवी व महेश पोद्दार का कार्यकाल पूरा

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 10 जून को होगा

रांची। झारखंड में राज्यसभा की रिक्त होने वाली दो सीटों के लिए चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत 24 मई को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 31 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून को नामांकन पत्र वापस लिये जा सकेंगे। 10 जून को मतदान की तारीख निर्धारित की गयी है। जरूरत पड़ने पर 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे मतों की गिनती होगी। 13 जून तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।

झारखंड में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार का कार्यकाल 7 जुलाई 2022 को पूरा हो रहा है। वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में तत्कालीन सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन ने दोनों ही सीट जीत ली थी। हालांकि दोनों सीटों पर भाजपा की जीत होने पर कई विवाद भी उत्पन्न हुए थे।

सत्तारूढ़ गठबंधन को एक सीट तय

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ जेएमएम-कांग्रेस-राजद गठबंधन के पास अभी 50 से अधिक सदस्यों का बहुमत है। ऐसे में एक सीट तो तय है, वहीं सरणस 20-21 वोटों की सहायता से दोनों सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश होगी।



राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव का एलान

नयी दिल्ली : राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का एलान कर दिया गया है। इसके लिए 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को चुनाव कराये जाएंगे। राज्यसभा में जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस नेता अब्बिका सोनी, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हैं। इन सभी का कार्यकाल 21 जून से 1 अगस्त के बीच समाप्त हो रहा है।

कहां से कितनी सीटें होंगी खाली

उत्तर प्रदेश में 11 सीटें खाली हो रही हैं। वहीं, तमिलनाडु-महाराष्ट्र से छह-छह, बिहार से पांच, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक से चार-चार, मध्य प्रदेश-ओडिशा से तीन-तीन, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हरियाणा से दो-दो और उत्तराखंड से एक सदस्य का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

बरही के पांच प्रखंडों में मतदान कल

संवाददाता
हजारीबाग : हजारीबाग त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 के तहत हजारीबाग जिले में प्रथम चरण का मतदान 14 मई को होना है। मतदान की अंतिम तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय सभागार में प्रेसवार्ता की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत (आम) निर्वाचन-2022 के तहत हजारीबाग जिले में तीन चरणों में मतदान एवं दो चरणों में मतगणना सम्पन्न किया जाना है। प्रथम चरण के तहत बरही अनुमण्डल क्षेत्र के पांच प्रखण्डों यथा चौपारग, बरही, बरकट्टा, चलकुशा एवं पदमा में 14 मई, 2022 को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक बैलेट बॉक्स के माध्यम से मतदान सम्पन्न होगा। वहीं 17 मई, 2022 को कृषि बाजार समिति प्रांगण में मतगणना का कार्य प्रातः 8:00 बजे प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पांच प्रखण्डों के 1048 बूथों



अन्तर्गत पांचों प्रखण्डों में मतदान सम्पन्न होने के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी की देखरेख में मतदान भेटी कृषि बाजार समिति, हजारीबाग स्थित वज्रगृह में सभी प्रपत्रों के साथ जमा किया जाएगा। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार ने पत्रकारों को निर्वाचन बैलेट मतपत्र के संबंध में बताया कि मतदान बैलेट मतपत्र के माध्यम से की जाएगी, जिनमें पंचायत समिति सदस्य के लिए हलका हरा रंग का मतपत्र, ग्राम पंचायत सदस्य स्फेद मतपत्र, मुखिया के लए हलका गुलाबी रंग तथा जिला परिषद सदस्य के हलका पीला रंग का मतपत्र में मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी। उन्होंने

पदमा प्रखण्ड के 113 वार्ड सदस्य के पद के विरूद्ध 26 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं।

इसी क्रम में बरही प्रखण्ड के 01 (एक) पंचायत समिति के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। शेष सभी पंचायत समिति के पद, सभी मुखिया के पद एवं सभी जिला परिषद के पद पर मतदान दिनांक 14 मई, 2022 को प्रातः 7:00 बजे से लेकर अपराह्न 3:00 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि बरही अनुमण्डल क्षेत्र के 5 प्रखण्डों में मतदान होंगे जिनमें कुल पंचायतों की संख्या 1048 हैं। जिनमें मुखिया के लिए 80 पद, पंचायत समिति सदस्य के लिए 103, वार्ड सदस्य के 1048 तथा जिला परिषद के 10 पदों के लिए मतदान होंगे। जिनमें 212238 पुरुष तथा 191811 महिला सहित कुल 404049 मतदाता अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे। इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए बतलाया गया कि प्रथम चरण चुनाव को सम्पन्न कराने के

ब्रीफ न्यूज

डॉ. संदीप मुखर्जी के निधन से एक कुशल चिकित्सक खो दिया : निसार खान



हजारीबाग : सर्वधर्म मानवता मंच ने शहर के जाने-माने चिकित्सक सह बंगाली दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष डॉ. संदीप मुखर्जी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मंच के संस्थापक सह केन्द्रीय अध्यक्ष निसार खान ने अपना शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि डॉ. मुखर्जी पेशे से तो चिकित्सक के अतिरिक्त एक प्रखर समाजसेवी थे। उनके निधन से एक कुशल चिकित्सक, प्रखर समाजसेवा, मिलनसार, मृदुभाषी तथा गरीब मरीजों का मसीहा खो दिया है। दिवंगत पुण्यत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा इस कठीन घड़ी में उनके परिजनों एवं स्नेहीजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

आरोग्यम हॉस्पिटल में मनाया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस



हजारीबाग : हजारीबाग के एकलौते सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एचजेडबी आरोग्यम सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर्बोल्लास पूर्वक मनाया गया। हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े सभी जनों ने नर्सिंग की पेशा से जुड़े कर्मियों के साथ केक काटकर और उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया और एक दूसरे को नर्स दिवस की बधाई दी एवं उनके जच्चे को सलाम किया। मौके पर हॉस्पिटल निदेशक हर्ष अजमेरा ने बताया की नर्स एक ऐसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक, मरीजों की देखभाल करने वाले सेवा कर्मी, महत्वपूर्ण विचारक और नवप्रवर्तनक हैं जो नर्सिंग के सम्मानजनक पेशा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के दिल और आत्मा हैं। उन्होंने समाज के सभी लोगों से इन्हें सम्मान देने का अपील भी किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल की एडमिस्ट्रेटर जया सिंह, श्रवण, राजेश, जितेंद्र, पवन, एके गौतम, तबरेज, अंसु कुमारी, अंसु तिवर्ी, बबिता कुमारी, नाजिया नवाज, मनीषा सरण, एष, मीतू सिंह, पमनी, सरालीन, अरुणा, अंजना प्रीति, विनीता सहित अन्य नर्सेस मौजूद रही।

विकास जैन की जमानत याचिका अस्वीकृत

हजारीबाग : हजारीबाग सदर थाना कांड संख्या 414/ 21 के मुख्य अभियुक्त विकास जैन जिस पर गबन जालसाजी जाली हस्ताक्षर अपराधिक साजिश एवं षड्यंत्र के आरोप में पुलिस ने न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल हजारीबाग भेज दिया था उसकी जमानत याचिका आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अस्वीकृत कर दी सरकारी वकील ने अपने पक्ष से दलिल प्रस्तुत करते हुए कहा कि विकास जैन ने 2020 में ही जेपी जैन की जमीन को शाहिद अख्तर को बेचकर पैसे प्राप्त कर लिए परंतु 8 महीने बाद जाली मनी रिसिप्ट बनाई तथा उस पर जेपी जैन एवं शिप्रा जैन के जाली हस्ताक्षर बनाये जेपी जैन द्वारा पैसें के दबाव के कारण विकास जैन ने 8 महीने के बाद जाली हस्ताक्षर कर जालसाज होने का प्रमाण दिया है मनी रिसीप्ट में पैसे किस माध्यम से दिए गए बैंक के माध्यम से चेक के माध्यम से फोन पे के माध्यम से इसका भी कोई जिक्र नहीं मिलता है जब पैसे 8 महीने पूर्व ही प्राप्त कर लिए गए थे तो विकास जैन ने 8 महीने बाद मनी रिसीप्ट क्यों बनाई इससे सत्यापित होता है कि इस मामले में जालसाजी गबन अपराधिक षड्यंत्र किया गया है इसी दलील को सुनते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जमानत को अस्वीकृत कर दिया. इस केस के अन्य अभियुक्त विकास जैन के ससुर भगवानदास और भाई रंजेश जैन उर्फ रिकू जैन फरार बताए जा रहे हैं पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।

डीसी ने किया सामाग्री कोषांग का निरीक्षण



हजारीबाग : हजारीबाग त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण मतदान की तिथि 14 मई निर्धारित है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने चुनावी प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों की अंतिम रूपरेखा का जायजा लेने सामग्री कोषांग पहुंची। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों का निरीक्षण किया। समाहरणालय भवन में बनाए गए सामग्री कोषांग का निरीक्षण करते हुए सभी तैयारियों की जानकारी ली, उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में हर छोटी मोटी सामग्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए सभी आवश्यक सामग्री व अन्य कार्य समयव पूर्ण हो या नितान्त आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने मतदानकर्मियों के लिए तैयार पैकेट की जानकारी ली। इसके अलावा चुनाव कार्य में प्रयोग होनेवाली सामग्री की जानकारी लेते हुए जवली गुणवत्ता के बारे में पूछताछ की। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से तय तमाम सामग्रीयों को पैकेट में डालना अनिवार्य है। उपायुक्त ने मतपत्र, पेपर की गुणवत्ता,अमिट स्थाई,पेपर सील, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका सहित अन्य सामग्री की जानकारी ली। मौके पर उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित,कोषांग के वरीय पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे।

नगर आयुक्त ने किया तालाबों की सफाई का निरीक्षण

हजारीबाग : हजारीबाग नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने निगम क्षेत्र के जबरा तालाब, जोड़ा तालाब हट्टरुब, कोल्हेरी तालाब,बेलाही तालाब, छहरवा डैम तालाब,तथा धोबीवा तालाब की सफाई तथा वहां चल रहे विभिन्न योजनाओं का निरक्षण किया। उन्होंने बरसात से पहले सभी तालाबों की सफाई तथा योजनाओ को पूर्ण करने का निर्देश अभिवन्ता को दिया। निरक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता श्री रमेश सिंह,सहायक अभियंता श्री राहुल माल्टो तथा कनीय अभियंता श्री रामचन्द्र उपरिस्थित थे।

मुखिया प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ किया जनसंपर्क



हजारीबाग : हजारीबाग इंचाक प्रखंड के पूर्णा इंचाक पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पंचायत के कई टोला में जनसंपर्क किया मौके पर भरत मेहता ने कहा कि 23 वर्ष देश का सेवा निर्यार्थ भाव से किए और ईमानदारी के साथ सेवानिवृत्त हुए पंचायत वासियों

के सहयोग और समर्थन के वजह से मुखिया पद का चुनाव पड़ रहे हैं और जिस तरह से 25 वर्ष देश का सेवा किए हैं उसी तरह पूरी ईमानदारी एवं पूरी पारदर्शिता के साथ पंचायत वासियों का सेवा करने का मौका मिल रहा है उन्होंने यह भी कहा कि अपनी 25 वर्ष की कमाई गांव की बेटियों को पढ़ाने के लिए कॉलेज का निर्माण भी कर चुके हैं यह चुनाव जीत और हार तो जनता तय करेगी चुनाव अगर जीत हैं तो पंचायत में चौमुखी विकास एवं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत सड़क बिरधा पेशन प्रधानमंत्री आवास को जरूरतमंदों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व के जनप्रतिनिधि पंचायत में सरकार के द्वारा मिला हुआ योजना की एक भी जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी वह अपने मर्जी से काम करते रहे जो आज धरातल पर एक भी योजना नहीं दिख रहा है।

छात्र हितों का हो रहा तिरस्कार : किशोरी

संवाददाता
हजारीबाग : हजारीबाग नव झारखंड फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा ने छात्रवृत्ति समय पर ना आने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मौजूद हालात में जहां हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करें अभी आगे चल कर उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। धन के अभाव में कई माता-पिता के साथ साथ युवाओं का सपना के अधूरा रह जाया करता था। जिस अधूरे सपने को पूरा करने का आधार बना था छात्रवृत्ति जिसके कारण उच्च शिक्षा के तर्फ गरीब मेधावी छात्रों का रुझान बढ़ा था। हर साल बड़े ही उम्मीदों के साथ गरीब छात्र सरकार द्वारा जारी ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरते हैं।



वर्ष 2020-2021 के लिए पी स्कॉलरशिप भराया गया था परंतु अभी तक हजारीबाग जिला के अधिकतम छात्रों के खते में छात्रवृत्ति की राशि नहीं आई है जिसको लेकर उनके चेहरे में चिंता साफ झलक रही हैं। फाउंडेशन के सदस्य व आईसेक्ट विश्विद्यालय

हजारीबाग के छात्र अमन हेंब्रम ने बताया कि हजारीबाग जैसे शहर में रहकर पढ़ाई करने वाले गरीब छात्रों के हितों की अनदेखी कर सरकार छात्रों के साथ सरोकार नहीं रखने वाला विजन को अपना रही है। छात्रवृत्ति समय पर ना आने के कारण कई सारे छात्र आक्रोशित हैं

जो निकट भविष्य में आंदोलन के तैयारी भी कर रहे हैं।

किशोरी राणा ने कहा , झारखंड जैसे संसाधन परिपूर्ण राज्य में छात्रों की पढ़ाई हेतु संपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। शिक्षित युवा शिक्षित समाज का निर्माण करता है और युवाओं के शिक्षा में बाधक बन कर सरकार अपने ही समाज के विकास में अवरोधक का काम कर रही है। चुनावी दौर में बड़े-बड़े वादा तो होता है लेकिन चुनाव के बाद वादा और इरादा दोनों बदल जाता है। सरकार के ऐसे दोहरी मानसिकता कारण ही झारखंड गर्त में गिर चुका है। कभी किसानों के साथ अन्याय होता है कभी शहीदों के साथ तो कभी छात्रों के साथ तो कैसे बनेगा हमारा सोना झारखण्ड।



हजारीबाग : हजारीबाग इंचाक प्रखंड के दरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी कुमारी रीना ने बुधवार को दरिया, पोखरिया ,जोगीडी, सहित कई गांव का दौरा किया। मौके पर उन्होंने कहा कि 2010 में ससुर अशोक यादव मुखिया पद के लिए चुनाव जीते थे और वह अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पंचायत में विकास किए थे उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी पंचायत वासियों का भरपूर समर्थन मिला है। इस चुनाव में भी पंचायत वासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है यह चुनाव जीतने के बाद पंचायत में चौमुखी विकास बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ना स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना एवं जल पात से डटकर पंचायत का विकास करना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसान की बेटी हूं और किसान के दुख दर्द को भलीभांति जानती हूं। वहीं मौके पर मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि पूर्व मुखिया अशोक यादव ने कहा कि 2010 में चुनाव जीतने के बाद कई लोगों को सहयोग किया हूं सरकार के पास फंड कम होने की वजह से पूरी विकास नहीं हो पाई है इस चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग एवं पंचायती राज लागू करना योजना की जानकारी देना पूरी पारदर्शिता के साथ पंचायत का विकास करना हमारा मुख्य मकसद है। मौके पर गीता देवी सरस्वती देवी मालती देवी समुदी देवी मनोरमा देवी शहीद सैकड़ी महिला चुनाव प्रचार में सामिल थीं।

सुरक्षा विभाग ने सीसीएल सीएचपी के पेलोडर से डंफर कोयला लोडिंग मामले की किया जांच

रामगढ़ : सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र मुख्यालय कार्यालय में गुरुवार को सुरक्षा विभाग हेड क्वार्टर रांची की टीम कोयला लोडिंग लूट जांच पड़ताल के लिए पहुंची। इस दौरान सुरक्षा विभाग रांची टीम के पदाधिकारियों ने स्थानीय सुरक्षा अरगड्डा क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वार्ता की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते मार्च माह के अंत में सीसीएल सिरका सीएचपी कोयला डंप से रात के अंधेरे में हाईवा डंपर में पेलोडर से कोयला लदाई तस्करी मामले की जांच पड़ताल सुरक्षा विभाग हेड क्वार्टर टीम के पदाधिकारियों ने किया। जिससे जुड़े जरूरी कागजातों और किए गए अब तक के कागजी कार्रवाईयों के बारे में गहनता से पूछताछ की गई। वहीं इस मामले में अरगड्डा के आरटीआईकर्ता के द्वारा सतर्कता विभाग दिल्ली व अन्य को अवगत कराने के बाद प्रबंधन के सुरक्षा विभाग रांची नॉंद से जागते हुए कार्रवाई में जुट गया हैं। बताया जाता है कि आरटीआईकर्ता के द्वारा सतर्कता विभाग दिल्ली को भी इसकी जानकारी दी गई हैं। इस आलोचन में सूचना विभाग को सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र ने जरूरी जवाब तक नहीं दिया हैं। सूत्र बताते है कि कुछ दिनों में केंद्रीय सूचना विभाग के द्वारा भी अरगड्डा क्षेत्र प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। यह कोयला गडबड़ी और तस्करी मामला जांच होने के बाद से ही घोटालेबाजों, माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया हैं। जबकि भ्रष्ट अधिकारी, गार्ड प्रभारी भी जांच कार्रवाई से अपने दामन को साफ करने में लग गए हैं। बहुत जल्द अरगड्डा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकता हैं।

यज्ञवेदी की परिक्रमा को ले उमड़े श्रद्धालु

रामगढ़ : कुजु नया बाजार में नवनिर्मित हनुमान मंदिर में जारी तीन दिवसीय श्री श्री 1008 श्री हनुमान एवं सर्वदेव प्रतिष्ठा महायज्ञ के दूसरे दिन पवनपुत्र हनुमान सहित अन्य देवी-देवताओं का नगर भ्रमण कराया गया। वाराणसी से आए यज्ञाचार्य विनोद मिश्र की देखरेख में पुरोहित उमाकांत पांडेय, दिवाकर पांडेय, यमुना पांडेय, बैजनाथ पांडेय, अयोध्या पांडेय,कैलाशपति मिश्र द्वारा रजमान बालेश्वर शर्मा, मनीषा कुमार सिंह, दिनेश केशरी, सुभाष सिंह, मिलल गुप्ता सबकीक को विधिवत पूजार्चना कराई गई। बाद में कुलों से सुसज्जित वाहन पर सवार देवी-देवताओं का गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण के दौरान भावा ध्वज के साथ जय श्री राम, जय वीर हनुमान के वर्योधष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान देवी-देवताओं के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

अस्पताल की नर्सें स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं: अनिल

रामगढ़ : अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ सबद्ध भारतीय मजदूर संघ रजरप्पा क्षेत्र के बैनर तले गुरुवार को स्थानीय सिल्वर जुबली अस्पताल में मौजूद सभी नर्सों एवं डॉक्टरों को सम्मान किया गया। इसका नेतृत्व क्षेत्रीय सचिव अनिल प्रसाद एवं अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष विशाल कुमार ने किया। इस दौरान उनकी कर्तव्य निष्ठा और सेवाभाव के लिए उनको आंग पखर देकर सम्मानित किय गया। मौके पर क्षेत्रीय सचिव अनिल प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नर्सें स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। उनकी कड़ी मेहनत व लगन के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने नर्सों के प्रयासों और कार्यों की प्रशंसा की। इससे पूर्व क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी निशिकांत होरो, डॉ एल विनिला, नर्स उर्मिला सिंग, सुरमिला तांती, लुशी किरण कंरकेटा ने विश्व की पहली नर्स फेलीरिस नाइटिंगेल के तस्वीर पर माल्यार्पण कर आगरवती दिखाया गया। इधर सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ रजरप्पा क्षेत्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाने से सिल्वर जुबली अस्पताल की नर्सों में भी काफी खुशी है। मौके पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, अमरनाथ वर्मा, मातीवर के अलावा नरेंद्र लाल दास, विकास रंजन, अमित कुमार सहित कई अस्पताल कर्मी मौजूद थे।

वेस्ट बोकारो डिविजन में मना पीएन बोस की 167 वीं जयंती

पीएन बोस की जयंती पर बच्चों ने उकेरी कलाकृतियां

संवाददाता
रामगढ़ : टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो डिवीजन ने भारत के पहले एकीकृत इस्पात संयंत्र टाटा स्टील की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान को याद करने के लिए प्रमथनाथ बोस (पीएन बोस) की 167 वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर वेस्ट बोकारो में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। दिन की शुरुआत पीएन बोस की डिजिटल श्रद्धांजलि के साथ हुई, जिसके बाद डीएवी पब्लिक स्कूल वेस्ट बोकारो में क्विज और ड्राइंग प्रतियोगिताएं

आयोजित की गईं। ड्राइंग प्रतियोगिता में कक्षा तीन से छह तक के 180 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा 3-4 के लिए विषय रस्कल की हरियाली, हमारी जिम्मेवारीर था और कक्षा 5-6 के लिए विषय रसस्टेनबल व्यवहार के साथ कला निर्माण था। इस अवसर पर भूगोल पर एक रोमांचक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रत्येक टीम में कक्षा 3-9 के छात्र शामिल थे। क्विज प्रतियोगिता के लिए टीम ए के



आरव पराशर,अनमोल, श्रेष्ठ, अवि्का पराशर, ख्याति और लिजा विजेता रहे। वहीं बी टीम के मनजोत, सकशेन हैं, सरिता,

सूर्यांश रोशनी, स्वर्णिम व विधि ने उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में कुल 35 विद्यार्थियों ने भाग

लिया। अपने अनुभव साझा करते हुए, कक्षा 7 की अवि्का पराशर ने कहा कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बहुत दिलचस्प थी क्योंकि सभी प्रश्न उन विषयों से थे जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। यह उत्साह और रोमांच से भरा था और हम सभी जवाब देने के लिए उत्सुक थे। मुझे खुशी है कि टाटा स्टील ने पीएन बोस की जयंती के अवसर पर एक रोमांचक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। हमने स्कूल में लगाई गई प्रदर्शनी के माध्यम से पीएन बोस के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। कक्षा 6

की छात्रा संजीवनी प्रमाणिक कक्षा 5 की छात्रा स्वस्तिका कुमारी कक्षा 4 की छात्रा अनामिका प्रमाणिक और कक्षा 3 की छात्रा श्रुति कुमारी को उनकी संबंधित कक्षाओं से ड्राइंग प्रतियोगिताओं का विजेता घोषित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वेस्ट बोकारो डिवीजन के कॉर्पोरेट कन्सुलिकेशन विभाग द्वारा किया गया था। टाटा डीएवी स्कूल में अग्रणी भू-विज्ञानी पीएन बोस के जीवन और यात्रा पर छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।

संपादकीय

भारत-जापान रिश्ते के 70 साल

28 अप्रैल को भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना के सात दशक पूरे हो गये। 28 अप्रैल, 1952 को एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किएयेथे। इन वर्षों में यह द्विपक्षीय साझेदारी न केवल आगे बढ़ी है, बल्कि वर्ष 2015 में हुई दिल्ली और टोक्यो विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदार बन गए हैं। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के चलते इस क्षेत्र को तेजी से बदलते शक्ति संतुलन की गतिशीलता का खतरा है। ऐसे में, यदि भारत और जापान को स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख वाहक बनना है, तो अपने सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले, दोनों देशों को चीन और उसके उदय के बारे में धारणा और कार्रवाई, दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटने के लिए सहयोगी और सुसंगत उपाय खोजने की जरूरत है। दूसरा, उन्हें यह तय करना चाहिए कि उनकी पहली रक्षा जरूरत क्या होगी। यदि ये ऐसा करते हैं, तो यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की मुखर कार्यवाइयों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत होगा। चीन के मौजूदा उदय को भारत और जापान किस तरह देखते हैं, इसमें इन दोनों देशों के चीन के साथ अतीत के अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए, भारत-चीन संबंध ने स्पष्ट और लंबे समय से चले आ रहे शक्ति के अंतर से आकार लिया है, जो 1962 के युद्ध में भारत की हार से पैदा हुआ है। दूसरी तरफ, जापान की साझेदारी को उसके सखियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों (1930 के दशक में चीन पर कब्जा करने की घटना सहित) के जरिये आकार दिया गया है। इसके अलावा, 1970 के दशक से, आर्थिक संबंधों का विस्तार करने को संकल्पित एक मजबूत चीनी लांबी को जापान की सतारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) में पैठ रही है। इसलिए चीन के साथ महत्वपूर्ण व्यापार एवं आर्थिक साझेदार होने की समानता के साथ उसके आक्रामक उदय से उत्पन्न खतरे के बावजूद टोक्यो और नयी दिल्ली की चीन के प्रति अपनी-अपनी धारणा में एक महत्वपूर्ण अंतर रहा है, या कम से कम चीन का सामना करने के प्रति अपेक्षाकृत अनिच्छुक रहा है, क्योंकि वह राजनीति को अर्थशास्त्र से अलग रखने की अपनी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। इसके विपरीत, भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि जापान के साथ सुरक्षा सहयोग किसी तीसरे देश की कीमत पर, या कम से कम चीन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। चीन के साथ लड़ाख में चल रहे संकट से भारत चीन के प्रति अश्वीर हुआ है, और वर्तमान आख्यान तेजी से बढ़ते तनाव और चीन के उदय को संतुलित करने पर केंद्रित है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, धारणा और कार्रवाई, दोनों में इस अंतर को पाटने का पहला प्रभावी तरीका यह है कि भारत और जापान अपने सुरक्षा संबंधों (जो पहले से ही अच्छी तरह काम कर रहा है) को मजबूत करें।

सामयिकी

गुलामी के अवशेषों से मुक्ति

डा. नितिन सहारिया

भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तो प्राप्त हुई किंतु अभी भी हम अंग्रेजीयत/ इस्लामियत को धारण किए हुए हैं। न्यायालय में अंग्रेजी-उर्दू का प्रयोग, वही अंग्रेजी जमाने के गुलामी के लालमी आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं और भी अनेकों विदेशी चीजों से हमने आज भी मुक्ति नहीं पाई है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 'स्व' का तंत्र बनाना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हो सका। हमने उन्हीं का गुणगान किया जिन्होंने हमें पराधीन (गुलाम) बनाया था। ऐसा लगता है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के पश्चात सत्ता गलत लोगों के हाथों में चली गई थी। तभी तो भारत आजतक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। एक तरफ आंशिक रूप से हमने कुछ सुधार अवश्य किए थे। गुलामी के चिह्न जॉर्ज पंचम की मूर्ति को इंडिया गेट से हटाया, मिंटो ब्रिज को शिवाजी ब्रिज, विक्टोरिया पार्क को महात्मा गांधी पार्क किया। कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे को हमने कोलकाता-चेन्नई-मुंबई किया। किन्तु अभी भी देश में बड़े सुधार की आवश्यकता है। भारत के संविधान की पूरी समीक्षा हो व वर्तमान की देश की प्रासंगिकता/ आवश्यकता के अनुरूप उसका स्वरूप का निर्धारण हो। ज्यादा लचीलेपन के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज भी भारत के न्याय के मंदिर में विदेशी अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। उच्च शिक्षा इंजीनियरिंग, तकनीकी, भारतीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि में अंग्रेजीयत की पैठ/दबदबा है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी गुलामी के अवशेष अभी भी देश में बाकी हैं। जरा विचार कीजिए जापान में शिक्षा जापानी भाषा में होती है। जर्मनी में जर्मन भाषा में, फ्रांस में फ्रेंच भाषा में, इंग्लैंड में अंग्रेजी में, रूस में रशियन भाषा में तो फिर भारत में शिक्षा हिंदी में क्यों नहीं? भारत की राजधानी दिल्ली का अद्भुत नजारा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कभी दिल्ली जाकर देखिए आपको ऐसा लगगा कि आप पाकिस्तान की राजधानी में आ गए हैं। अकबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब-जहांगीर -शाहजहां रोड, सराय काले खांब बस स्टॉप, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, मुगल गार्डन, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, आपसफ अली रोड। क्या है ये सब? भारत आजाद हुआ है कि नहीं? अथवा देश की स्वतंत्रता के नाम पर छलावा हुआ है? यदि छलावा नहीं तो फिर यह दृश्य क्या है? यह देश में चल क्या रहा है? इसके विपरीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तो कहीं लेशमात्र भी भारत की झलक/ झांकी नहीं दिखलाई देती, फिर भारत में यह सब क्यों? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। कुछ प्रश्नों पर जरा हम विचार करें -लुटेरों (अताताइयों के) नाम पर देश की राजधानी के मांगों के नाम क्यों? लुटेरों के नाम पर देश की राजधानी के मांगों का नामकरण आखिर किसने किया? क्यों किया? दिल्ली भारत की राजधानी है या पाकिस्तान की? देश में आजादी के 75 वर्ष बाद भी गुलामी के अवशेष शेष क्यों? कौन देशाडहियों से प्रेम कर रहा /किस है? खगोलीय वेधशाला का नाम बदलकर आखिर कुतुब मीनार किसने करवाया? किसने तेजो महालय (शिव मंदिर) को ताम्रमहल लिखवाया इतिहास की पुस्तकों में? वाराणसी में ज्ञानवापी जब मंदिर है तो फिर मस्जिद किसने बनाई? किसने इतिहास की पुस्तकों में उसे झुठा ज्ञानवापी मस्जिद लिखवाया? किसने इतिहास में इतने झुठे/मिथक गढ़े/ लिखवाए?



गिरिश जोशी

भगवान बुद्ध ने अपने जीवनकाल में कभी वेदों का विरोध नहीं किया लेकिन उस समय वे लोग जो वेदों का त्रुटिपूर्ण प्रतिपादन कर मनमाने कर्म जैसे हिंसा तथा पशुबलि जैसी कुप्रथा में लिप्त हो गए थे उनका विरोध किया था। भगवान बुद्ध की संकलित वाणी सुननपात 292 में लिख्या- विद्वा च वेदेहि समेच्च व धम्मं, न उच्चावचं गच्छति भूपरिपइजे। इसका अर्थ पं. धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड अपने गन्ध वेदों का यथार्थ स्वरूप में करते हैं- जो विद्वान वेदों द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है। उसकी ऐसी डांवाडोल अवस्था नहीं होती। धम्मपीति सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा। अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो।।

अभिव्यक्ति

भगवान बुद्ध व सनातन दर्शन के अंतर्संबंध

भगवान बुद्ध और बौद्ध पंथ के विषय में अनेक विमर्शों के माध्यम से सनातन और बौद्ध दर्शन के बीच मतभिन्नता का अस्तित्व खड़ा किया गया है। इस विमर्श से हटकर एक अलग दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध और सनातन दर्शन के अन्तर्सम्बन्धों को देखने का प्रयास करते हैं।

भारत देश की विशेषता है, जब-जब समाज धर्माचरण के मार्ग से विचलित हो जाता है, सनातन के शाश्वत सिद्धांतों की समाज को विस्मृति हो जाती है, समय काल परिस्थितिवश सामाजिक व्यवस्था में धर्म का त्रुटिपूर्ण विवेचन होने लगता है इस कारण से विभिन्न प्रकार की जटिल समस्याएं सामाजिक जीवन में व्याप्त हो जाती है, तब-तब इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उच्चस्तर की चेतना का धरती पर अवतरण होता है। इस प्रकार अवतरित हुई चेतनाओं को ही अपने यहां अतार कहा गया है। सृष्टि परिचालन की व्यवस्था के बारे में सनातन दृष्टि में ब्रह्मा-सृजन, शिव-विसर्जन और विष्णु पालन का काम करते हैं। जिसके पास व्यवस्थाओं के संचालन का काम होता है उसे ही व्यवस्थाओं में आने वाली गड़बड़ी को ठीक करने का भी दायित्व वहन करना पड़ता है। इसलिए जब भी व्यवस्था तंत्र में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता होती है उस समस्या की प्रकृति के अनुसार उसे ठीक करने के लिए भगवान विष्णु एक अलग अवतार में विलक्षण दृष्टिकोण के साथ हमारे मध्य उपस्थित होते हैं। भगवान बुद्ध की मूल चेतना को आद्य शंकराचार्यजी ने पहचाना था। इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध को दशावतार में एक अवतार माना है।

भगवान बुद्ध की उच्चस्तरीय चेतना को आचार्य शंकर ही पहचान सकते थे। यहाँ हम बौद्ध दर्शन और सनातन परंपराओं के बीच किस प्रकार का संबंध है, उसका विचार करेंगे। भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित मार्ग में त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ, दिए गए हैं। सनातन में भी तीन योगों का प्रावधान है- कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग। बुद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य हैं। आर्य सनातन परंपरा का गुणवाचक विशेषण है। सनातन में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं। बुद्ध दर्शन में पंचशील है-1.बुट न बोलाना 2. हिंसा न करना 3. चोरी न करना 4. व्यभिचार न करना 5. नशा न

करना। सनातन परंपरा में पांच यम है- सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग सम्यकदृष्टि, सम्यक, सम्यक्वचन, सम्यक्कर्म, सम्यकआजीविका, सम्यक्व्यायाम, सम्यक्संमृति और सम्यक्समाधि का प्रवर्तन किया। सनातन परंपरा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम,

अत्यन्त प्रसन्नचित्त से सुखपूर्वक सोता है। पण्डितजन सदा आर्योपदिष्ट धर्म में रत रहते हैं। न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा धर्मोति ब्राह्मणो। यम्हि सच्चं च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो।। (धम्मपद पृ. 140-141) अर्थात् न जन्म के कारण, न गोत्र के कारण, न जटा धारण के कारण ही कोई ब्राह्मण होता है।



प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि अष्टांग योग के माध्यम से सत्य को जानने का मार्ग बतलाया गया है। दोनों मार्गों का लक्ष्य समाधि ही है। सनातन परंपरा में साधना के लिए चार साधन चतुष्टय- नित्यानित्यवस्तुविवेक,वैराग्य, षट्सम्मति का अर्जन तथा मुमुक्षता और छः संपत्ति -शम,दम,श्रद्धा,समाधान,उपरति और तितिक्षा कुल दस बातों का साधक में होना जरूरी बताया गया है तो बौद्ध दर्शन में दस परिमिताएं - दान, शील, नैक्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा को आवश्यक बताया गया है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवनकाल में कभी वेदों का विरोध नहीं किया लेकिन उस समय वे लोग जो वेदों का त्रुटिपूर्ण प्रतिपादन कर मनमाने कर्म जैसे हिंसा तथा पशुबलि जैसी कुप्रथा में लिप्त हो गए थे उनका विरोध किया था। भगवान बुद्ध की संकलित वाणी सुत्तनपात 292 में लिखा- विद्वा च वेदेहि समेच्च व धम्मं, न उच्चावचं गच्छति भूपरिपइजे। इसका अर्थ पं. धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड अपने ग्रन्थ वेदों का यथार्थ स्वरूप में करते हैं- जो विद्वान वेदों द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है। उसकी ऐसी डांवाडोल अवस्था नहीं होती। धम्मपीति सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा। अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो।। (धम्मपद पृ. 114-15) अर्थात् धर्म में आनन्द मानने वाला पुरुष

जिसमें सत्य है, जिसमें धर्म है, वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है। भगवान बुद्ध ने विषयश्चना नामक साधना की तकनीक को वेदों से ही प्राप्त कर पुनः प्रतिस्थापित किया और उसके माध्यम से साधना कर बुद्धत्व को प्राप्त हुए। अखिल सृष्टि के सत्य स्वरूप का वर्णन करते हुए बुद्ध कहते हैं-सबसे पज्जलितो लोको,सब्वो लोको पर्कपितो अर्थात मुझे सृष्टि का माया से अनावृत सत्य स्वरूप ये दिखा की सारा लोक पज्जलित यानी प्रकाश के स्वरूप में है और सर्वत्र मात्र प्रकन यानि केवल तरंगे ही तरंगे है। इस सृष्टि का वास्तविक स्वरूप प्रकाश और तरंगे मात्र है। हमें दृश्यमान स्वरूप में जो जगत दिखाई पड़ता है वो उस प्रकाश तथा तरंगों की घनीभूत अभिव्यक्ति है,वह वास्तविक नहीं है। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था-ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या जीवोब्रम्हैव नापरह। भगवान बुद्ध ने अपने अनुभव का आधार पर कहा- अत्ताहि अत्तनो नथो को हि नाथो परो सिंया अत्तनं व सुदन्तेन,नाथं लभति दुल्लभं। अर्थात मैं स्वयं अपना स्वामी हूँ। सुयोग्य पद्धति से जानने के प्रयास करने पर ह्यनाथं लभति दुल्लभं से दुर्लभ नाथ (ब्रम्ह) पद प्राप्त होता है। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य ने महावाक्य में अभिव्यक्त किया- अहम् ब्रह्मास्मि। दोनों का गंतव्य एक ही था केवल मार्ग अलग था। भगवान बुद्ध के मन में दुःखों के कारण

का निवारण विचार था। भगवान बुद्ध के अनुसार हमारे दुःखों का कारण हमारा इस जगत के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, विचार आदि के प्रति अनुराग या द्वेष होता है। बुद्ध के अनुसार ये सारी चीजें अनित्य हैं जो पल-प्रतिपल समाप्त हो हो रही है, प्रिय के प्रति अनुराग और अप्रिय के प्रति द्वेष हमारे दुःखों का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध ने इस संसार की हर बात को अनित्य प्रकृति का होने के कारण उस पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना कर अस्तित्व को शून्य के रूप में स्वीकार कर तटस्थता के मार्ग का अनुसरण किया और सत्य तक पहुंचे। इस संबंध में आदि गुरु शंकराचार्य के दृष्टिकोण को देखें तो इस विश्वप्रपंच को देखकर उनके मन में प्रश्न उठे- कसवम कोरहम कुतः अयात, को में जन्मी को में तातः यानि में कहाँ और क्यों आया हूँ? मेरे वास्तविक माता-पिता कौन है? मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? इस सृष्टि का रहस्य क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वे भी वेदों में वर्णित अन्तर् की साधना का अनुसरण कर सत्य तक पहुंचे। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में शून्य और अन्त के बीच भारी अंतर है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। लेकिन दृष्टि से देखें कि अनादि और अन्त है उसकी दृष्टि से देखें तो उसके लिए शून्य और अन्त एक ही रस्सी के दो छोर जैसे ही हैं। गणित के विद्यार्थियों को शून्य और अन्त का संबंध बड़ी आसानी से समझ में आता है। यदि किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो परिणाम अन्त प्राप्त होता है और यदि किसी संख्या को अन्त से भाग दिया जाए तो परिणाम में शून्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ है अर्थ है यदि हम शून्य का विचार लेकर चलें या अन्त की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़े अंततोगत्वा इस सत्यान्वेषण की प्रमेय का हल परमसत्य के रूप में ही प्राप्त होगा। इसी देश के सत्यान्वेषी मनीषियों ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा है- एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति। भगवान बुद्ध इस देश में अवतरित हुए विप्र श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं में से एक हैं जिन्होंने उसी सनातन सत्य को एक अलग मार्ग से खोज कर दुनिया के सामने रखा है।

(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव हैं।)

सूचना के अधिकार कानून से बाहर हो सेना

जरा एक बात पर गौर करें कि सूचना के अधिकार की आड़ में भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर कुछ खास तत्वों में उत्सुकता किसलिए हो सकती है? क्या सेना के कामकाज की जानकारीयां सार्वजनिक करनी चाहिए? सेना से संबंधित जानकारीयां सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सेना की विभिन्न इकाइयों, एजेंसियों तथा छावनियां से मांगने वाले कौन लोग हैं? ये तमाम सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि इधर देखने में आ रहा है कि कुछ तत्व सेना की अति संवेदशील एवं महत्वपूर्ण जानकारीयां को हासिल करने में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। इन सब वजहों से सेना का तंत्र भी चौकन्ना हो गया। वह सारी स्थिति पर नजर रख रहा है। उसकी तरफ से हाल ही में यह भी मांग हुई है कि सेना को आरटीआई कानून से बाहर रखा जाए। ये मांग सच में बहुत ही सार्थक है तथा संकेत दे रही कि मामला कितना गंभीर है।

पिछली 28 अप्रैल के केन्द्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस बात पर गंभीर चिंता जताई गई कि आरटीआई के नाम पर सेना की अहम जानकारीयां मांगी जा रही हैं। यह बैठक सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के रिटायर होने से दो दिन पहले हुई थी। सेना की तरफ से उपर्युक्त मांग को लेकर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस पर सरकार को देश की आंतरिक सुरक्षा तथा सेना के कामकाज को गुप्त रखने के अधिकार के आलोक में निर्णय लेना होगा। निश्चय ही देश के नागरिकों को आरटीआई कानून के तहत सूचना पाने के अधिकारों की सीमाएं हैं। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनौ हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन जनता को यह अधिकार तो कतई नहीं दिया जा सकता

कि वह देश की सुरक्षा और शत्रु का मुकाबला के लिए की जा रही तैयारियों की ही जानकारीयां मांगने लगे। जाहिर है, ये सब



वे शांतिर लोग करते हैं जिनके इरादे नेक नहीं होते। ये कौन नहीं जानता कि हमारे यहां सेना की जासूसी करने वाले जयचंद और मीर जाफर भी जगह-जगह मौजूद हैं। हमें सेना के अंदर ही छिपे कुछ गद्दारों से लेकर कुछ तथाकथित पत्रकार आदि शामिल हैं। ये आरटीआई के माध्यम से धीरे-धीरे सूचनाएं निकालने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। इन्हें अपने आकाओं से मोटा पैसा जो मिलता है। इसलिए ये अपनी मातृभूमि का भी सौदा करने से पीछे नहीं हटते। इनका जमीर मर चुका है। इसलिए यह जायज मांग तो ये भी हो रही है कि इंटीलिजेंस ब्यूरो, रॉ, नेशनल सिक्युरिटी गार्ड्स (एनएसजी), सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय सुरक्षा बल पुलिस जैसे कुछ और सरकारी विभागों को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया जाए या फिर यहां से सूचनाएं प्राप्त करने की सीमा तय कर दी जायें। मतलब सिर्फ इन विभागों से जुड़े रहे मुलाजिम इनसे अपनी पेंशन और नौकरी संबंधी जानकारीयां आदि ले लें। आपको याद ही होगा कि पिछले साल चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में राजधानी के एक कथित वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा को पकड़ लिया गया था। राजीव शर्मा के बारे में

पता चला था कि वह आरटीआई से जानकारीयां निकाल कर चीन को सप्लाई करता था। उसे ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट (ओएसएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसने सेना से जुड़े कई राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सूचनाओं वाले दस्तावेज चीन को दिए थे। चीन को संवेदनशील सूचनाएं उपलब्ध कराने की एवज में उसे मोटी रकम मिलती थी। दरअसल एक ब्रेदर शानदार कानून को कुछ शांतिर तत्व दुरुपयोग करने लगे हैं। इसलिए ही देश के उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर, 2019 को कहा था कि आरटीआई का दुरुपयोग रोकने और इसके माध्यम से आपराधिक घमकी पर रोकथाम के लिए सूचना का अधिकार कानून के लिए दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है। तब प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा था, हम आरटीआई कानून के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हमें लगता है कि इसके नियमन के लिए किसी प्रकार के दिशा-निर्देश बनाना जरूरी है। पीठ ने कहा, कुछ लोग आरटीआई दायित्व करने के विषय से किसी तरह संबंधित नहीं होते। यह कई बार आपराधिक घमकी की तरह होता है, जिसे ब्रैक्मेल भी कहा जा सकता है। देखिए, यह सरकार को तो पता ही है कि आरटीआई के तहत आवेदकों की बाढ़-सी आ गई है। बहुत से लोग अनाप-शापा सवाल भी पूछते रहते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिकार का गलत इस्तेमाल न हो। मुझे केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी बता रहे थे कि उनके विभाग से हर साल दर्जनों आरटीआई में यही पूछा जाता है कि गांधीजी को सबसे पहले महात्मा किसने बोला ? संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही काम करता है गांधी स्मृति और दर्शन समिति। यानी फिलजुल की आरटीआई के तहत पूछे गए सवालों के जवाब देने में सरकारी बाबुओं का बहुत-सा वक्त गुजर जाता है।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, संभकार और पूर्व सांसद हैं।)

श्रीलंका संकट में क्यों फंसा, भारत के लिए भी सबक



विक्रम उपाध्याय

श्रीलंका में जो हो रहा है, भयावह है। केवल वहां के नागरिकों के लिए यह महा विपत्ति काल नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी एक सबक है। किसी देश में जब घनघोर परिवाक्वाद हो, सत्ता में आने या बने रहने के लिए अर्थव्यवस्था के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ लोकलुभावन नीतियां बनें, जब राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर सत्ता में बैठे लोग अपने हितों की चिंता करें और जो शासक दुर्गम और दोस्त में फर्क ना समझ पाए तो वह श्रीलंका हो जाता है।

भारत के दक्षिणी छोर पर बसे द्वीप श्रीलंका के सामने ईंधन, भोजन, दवा, घर की अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं का संकट है। पेट्रोल-डीजल मिल नहीं रहे। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात कर दी गई है। 13 घंटे की लंबी बिजली कटौती हो रही है। सार्वजनिक परिवहन समय से चल नहीं रहे हैं। त्यागपत्र दे चुके, प्रधानमंत्री अपनी जान बचाने के लिए श्रीलंका नेवी के बंकर में छुपे हुए हैं। पूरे श्रीलंका में व्यापक सामाजिक अशांति फैली हुई है। श्रीलंका की समस्या बहुत गहरी है और इसका हल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है

आखिर श्रीलंका इस बुरी स्थिति में पहुंचा कैसे। यह संकट रातों रात वहीं नहीं उत्पन्न हुआ। पिछले तीन साल से श्रीलंका आर्थिक संकट की ओर लगातार बढ़ता आ रहा था, लेकिन समय पर स्थिति संभालने के बजाय मौजूदा शासकों ने इसे गटर में जाने दिया। पर्यटन उद्योग पर मुख्य रूप से आश्रित श्रीलंका को यह मालूम था कि कोविड 19 के बाद दुनिया बंद कर दी गई है, इसलिए जरूरी था कि वह अपनी आय के अन्य स्रोतों पर काम करें, लेकिन श्रीलंका ने काम के बजाय कर्ज का रास्ता, वह भी मुख्य रूप से चीन से कर्ज के रास्ते को चुना। श्रीलंका के आय के स्रोत खत्म हो रहे थे और कर्जों पर ब्याज एवं आयात के खर्च बढ़ रहे थे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता गया और जरूरी सामान के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा मिलना बंद होने लगा।

श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 2019 के अंत में 7.9 अरब डॉलर था जो मार्च 2022 में घटकर 1.9 अरब डॉलर रह गया। केवल दो ढाई वर्षों में ही लगभग 70% विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। जबकि श्रीलंका की देनदारी बहुत ज्यादा है। इसी साल यानी 2022 में ही श्रीलंका को विदेशी कर्ज के मद में 4 अरब डॉलर लौटाने हैं। एक अरब डॉलर उसे सोवरेन बॉंड के पुनर्भुगतान के रूप में लौटाना है। अंग्रेजी एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार इस साल श्रीलंका की कुल विदेशी मुद्रा में देनदारी 8.4 अरब डॉलर की है। जाहिर है श्रीलंका इसमें विफल रहेगा और आने



वाले महीनों में स्थिति और खराब होने की आशंका रहेगी। समाज में और अराजकता फैल सकती है जब देश को आवश्यक वस्तुओं का और अधिक संकट का सामना करना पड़ेगा।

ये तो ताजा स्थिति है, लेकिन इस

स्थिति तक श्रीलंका पहुंचा कैसे?

विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके लिए सीधे-सीधे राजपक्ष परिवार जिम्मेदार है। श्रीलंका में पिछला चुनाव नवंबर 2019 में हुआ था। उस चुनाव में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष चुनाव जीत गए। जीतते ही उन्होंने पहले से खस्ताहाल में चल रहे श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के बजाय राजस्व हानि वाले फैसले लागू कर दिए। जनता को खुश करने के नाम पर उन्होंने पहले

से लागू राष्ट्र-निर्माण कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। वेट दर को भी 15 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया। विदहोल्लिंग टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और बैंक डेबिट टैक्स को हटा दिया गया।

2021 में श्रीलंका का कर्ज जीडीपी के मुकाबले 101 प्रतिशत था और बजट घाटा 11.10 प्रतिशत का था। नतीजा कर्ज का बोझ हर रोज बढ़ता गया। अपने निर्यात को बढ़ावा देने के बजाय, अपने भंडार को भरने के लिए श्रीलंका सरकार ने विदेशी धन उधार लिया। नतीजा विदेशी कर्ज तो बढ़ता गया, स्थानीय उद्योग भी नजरदाज होते चले गए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार श्रीलंका विदेशी कर्ज 25 अरब डॉलर से भी अधिक है।

किसी भी देश का आर्थिक स्तंभ वहां की खेती होती है। यदि कृषि क्षेत्र अपना प्रदर्शन सुधार लेता है, तो खाद्यान्न समस्या काफी हद तक काबू में रहती है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, लेकिन वर्तमान सरकार की एक नीति ने चाय की खेती को एकदम से बबादी की कगार पर पहुंचा दिया। अचानक अप्रैल 2021 में श्रीलंका की सरकार ने राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के साथ अनावश्यक प्रयोग करते हुए श्रीलंका को पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया और रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह एक विनाशकारी कदम साबित हुआ। खेती बुरी तरह प्रभावित हुई और देश में खाद्य मुद्रास्फोति काफी बढ़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि राजपक्ष सरकार को आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। बाद में प्रतिबंध वापस लिया गया और भारत एवं चीन से रासायनिक खादों की तत्काल खेप भेजी गई। तब तक श्रीलंका के चाय और रबर के निर्यात को काफी नुकसान पहुंच चुका था। राजपक्ष सरकार ने केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं, विदेशी मामलों में भी काफी कमजोर नीतियों को लागू किया। खासकर चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने में भारत के हितों के नजरंदाज किया गया। चीन ने श्रीलंका को कर्ज के दाल में फंसा लिया और 2015 में कर्ज न चुकाने के एवज में श्रीलंका को हंबन्टोटा बंदरगाह चीन को 99 वर्षों के लिए लीज पर देना पड़ा। हंबन्टोटा बंदरगाह के साथ साथ राजपक्ष हवाई अड्डे के निर्माण के लिए

चीन से 2 बिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज लिया गया। अब वही राजपक्ष हवाई अड्डा खाली पड़ा है।

दूसरी तरफ भारत लगातार श्रीलंका को मानवीय और पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए सहायता पहुंचा रहा है। भारत ने एफडीआई के रूप में श्रीलंका को 2005 से 2019 तक लगभग 1.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया। चीन और ब्रिटेन के बाद, भारत 2019 में भी श्रीलंका के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा। कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका में निवेश किया है। भारत कोलंबो बंदरगाह को भी काफी कर्माई करवाता है। वैश्विक व्यापार में कोलंबो भारत के लिए एक ट्रांस-शिपमेंट हब है। यहां से शिपमेंट कार्गो का साठ प्रतिशत बंदरगाह भारत द्वारा निर्यात किया जाता है।

और अंत में श्रीलंका के वर्तमान हालात से यह सबक सीखा जा सकता है कि जब सत्ता पर परिवारवाद हावी हो जाता है तो क्या दुष्परिणाम मिलता है। चुनाव जीतने के बाद गोटाबाया राजपक्ष खुद राष्ट्रपति बने तो अंतरे भाई महिंद्रा राजपक्ष को प्रधानमंत्री बना दिया। तुलसी राजपक्ष वित्त मंत्री बना दिए गए तो महिंद्रा राजपक्ष के पुत्र नमल को उनके उत्तराधिकारी के रूप खेले मंत्री बना दिया गया। महिंद्रा राजपक्ष के सीए अनजित निवाई को श्रीलंका के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बना दिया गया। जाहिर है कि भाई भतीजावाद के इस शासन का हश्य नहीं होना था।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

